STATUTORY RESOLUTION

Approving Proclamation issued by President on January 19, 2009, in relation to State of Jharkhand

MOTION *contd.*

Recommending to the President Revocation of Proclamation issued on January 19, 2009, in relation to State of Jharkhand

GOVERNMENT BILLS *contd.*

The Jharkhand Appropriation (Vote on account) Bill, 2009

and

The Jharkhand Appropriation Bill, 2009

श्री यशवंत सिन्हा: सर, मैं कह रहा था कि यह जो श्रीमती पूजा सिंहल हैं, उनका दो महीने में नौ बार ट्रांस्फर किया गया। She was transferred for nine times in two months. She is very competent officer. I know her personally. जब इस तरह से सरकारें होती हैं तथा मधु कोड़ा की सरकार बन गई तो इससे क्या फर्क पड़ता है? शिबू सोरन की सरकार बन गई तो क्या फर्क पड़ता है?

सुश्री मैबल रिबैलो: जब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी, क्या फर्क पड़ा?

श्री यशवंत सिन्हा: मैं बतलाता हूं कि क्या फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि झारखंड सरकार का जो हेलीकोप्टर है, उसको बैलगाड़ी समझ लिया और जो चाहे उसको मिस-यूज कर रहा है। तो किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर दिया कि इस बात की जांच हो कि वे लोग कौन हैं, जो हेलीकोप्टर पर चढ़े? अब वे सब बातें खुल रही हैं। मंत्रियों के रिश्तेदार, मंत्रियों के चमचे, मंत्रियों के ओंगे-पोंगे सारे लोग ही हेलीकोप्टर में घूम रहे हैं। अभी रांची के हाई कोर्ट ने कहा है कि "Why shouldn't there be a CBI inquiry into the misuse of helicopter." यह होता है। जब एन0डी0ए0 की सरकार थी तो उन्होंने नहीं कहा कि हेलीकोप्टर के मिस-यूज की सी0बी0आई0 जांच कराओ। तब पूजा सिंहल का नौ बार ट्रांसफर नहीं हुआ। दूसरे, वह अब फेल्ड स्टेट है, लॉ एंड आर्डर मटियामेट, नक्सलवाद चरम सीमा पर है। अभी यहां पर गृह मंत्री महोदय क्वैश्चन ऑवर में कह रहे थे कि विल पॉवर होना चाहिए, झारखंड में विल पॉवर नहीं है इसलिए हम नक्सलियों से नहीं लड़ सकते, इसलिए वहां नक्सलिज्म फैल रहा है। जैसा कि हमको मैबल जी ने करेक्ट किया कि वहां 24 में से 20 जिले आज एफेक्टेड हैं। उस पर आलम यह है कि शहरों में नक्सली घूम रहे हैं, हथियार लेकर घूम रहे हैं। मैं शहर के कुछ बाहर रहता हूं और वहां पर वे इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं। मैं जिस बूथ पर वोट देता हूं, अगर उस बूथ पर सी0आर0पी0एफ0 का पहरा न हो तो वोट नहीं होगा। तो हर कदम पर वहां यह स्थिति है।

अच्छा अब आप देखिए फाइनेंसियल मेनेजमेंट का। इस साल का प्लान आठ हजार दो सौ करोड़ रुपए का था। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अखबार वालों ने यह आंकड़े छापे कि 31 दिसम्बर तक मात्र तीन हजार तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए। बाकी पैसा खर्च नहीं हुआ। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद दो दिन के भीतर गवर्नर साहब ने सोलह सौ करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मैं चाहूंगा कि यहां वित्त मंत्री और राज्य मंत्री शकील साहब बैठे हैं, तो दोनों में से कोई क्लेरिफाइ करे। जहां नौ महीने में तीन हजार तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं दो दिन में सोलह सौ करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए? अब यह सोलह सौ करोड़ रुपए कहां गए, कैसे खर्च हुए, उसका कोई हिसाब नहीं है। आज के दिन में स्थिति यह है कि प्लान के फंड का चार हजार करोड़

रुपया अभी भी खर्च नहीं हुआ है, जबकि दिन बहुत कम बचे हैं। फिर झारखंड में मार्च लूट होगी। मार्च लूट हो रही है। मैं कहूंगा कि चूंकि राष्ट्रपति शासन लगा है, तो भारत सरकार के मंत्रियों का यह दायित्व बनता है कि वे सुनिश्चित करें कि झारखंड में मार्च लूट नहीं होगी। यह गाढ़े कमाई के पैसे हैं और इसलिए अगर इसका दुरुपयोग होता है, पैसे बेकार में जाते हैं तो यह स्वीकार्य नहीं है। उपसभापति जी, मैं जो निर्दलीयों की बात कर रहा था, उन सभी के ऊपर आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा चल रहा है और मुकदमा झारखंड सरकार ने नहीं किया है, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनकी जांच करो, तब जाकर एफ.आई.आर. रजिस्टर्ड हुई है। उनके यहां पर छापे पड़े हैं। देश भर में चारों तरफ चर्चा थी कि वहां पर मंत्री नोट गिनने की मशीन अपने घरों में रखे हुए हैं। नोट गिनने की मशीन कि भाई कोई जाली नोट न दे दे, कोई कम नोट न दे दे, इसलिए नोट गिनने की मशीन अपने घर में रखो और फटाफट नोट गिनाता था, अंदर जाता था। यह स्थिति थी। अब उन सब के खिलाफ, जिसमें पूर्व मुख्य मंत्री भी शामिल हैं, आय से अधिक सम्पत्ति रखने के मामले दर्ज हैं और इन्क्वायरी चल रही है, छापे पड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ मिलकर फिर सरकार बना रहे हैं। शिबू सोरेन जी ने कहा कि मधु कोड़ा की बिल्कुल बेकार सरकार है। जब वह खुद मुख्य मंत्री बने, तो मधु कोड़ा को हटाकर सारे मंत्रियों को रखा। उसी सरकार को रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, सड़े-गले सारे लोग फिर से उनकी सरकार में दोबारा मंत्री बन गए। आज इस सदन में अरुण शौरी जी जिक्र कर रहे थे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की। हम लोग गांवों में घूमते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि गांव में बिजली नहीं है, बिजली ले आओ। आपको पता है कि झारखंड के 32 हजार गांव में से 27 हजार गांव ऐसे थे, जिनमें कभी बिजली नहीं पहुंची। उन 27 हजार के बाद बाकी जो पांच हजार गांव थे, उनमें बिजली पहुंची थी, लेकिन अरुण शौरी जी ने जैसा कहा था कि उनमें से अधिकांश डि-इलेक्ट्रिफाई हो गयी। कभी उन गांवों में दस साल, पन्द्रह साल, बीस साल पहले, उनके तार चोर काट कर ले गए, खम्भे उठाकर ले गए, ट्रांसफारमर उठाकर ले गए, फिर कभी बिजली नहीं आई। अब वहां पर क्या है ? आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि झारखंड का जो बिजली बोर्ड है, उसमें आठ वर्षों में सात चेयरमैन बदले गए हैं। वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, उनकी उम्र शायद 85 वर्ष होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो वह 85 की उम्र के नहीं हैं, तो 83 की उम्र के होंगे। ...**(व्यवधान)**...

सुश्री मैबल रिबैलो: उनकी उम्र 82 वर्ष हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Ms. Mabel, you are wrong. It is 28. He is 28-year old.

श्री यशवंत सिन्हा: मैं एक बार फिर रिबैलो जी की बात मान लेता हूं। वह 85 वर्ष के नहीं हैं, तो 82 वर्ष के होंगे। ...**(व्यवधान)**...

सुश्री मैबल रिबैलो: सर, 70 साल, 80 साल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं, तो 82 वर्ष का व्यक्ति झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है।...(व्यवधान)...

SHRI YASHWANT SINHA: Without sounding vulgar, I would like to say that they should have five bypass surgeries also. अच्छा, अब हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों डाला गया? इनको किस हालत पर चेयरमैन बनाते हो? सरकार ने कहा, "He is Chairman only until further orders." अरे भाई further orders का क्या मतलब हुआ? हाई कोर्ट ने पूछा कि कल, परसों कब हटाया जाएगा, कब तक रहेंगे ? अंधेर नगरी चौपट राजा। ...**(व्यवधान)**...

सुश्री मैबल रिबैलो: सर, उसकी हियरिंग है, उसमें कुछ न कुछ होगा। आप चिंता मत करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री यशवंत सिन्हा: उपसभापति महोदय, मैं दूसरा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, हाउस के सामने NREGA स्कीम है। इसके बारे में अभी प्रणब जी भी कह रहे थे, सभी

लोग कह रहे थे, अरुण शौरी जी ने जो आंकड़े दिए, उनको नजरअंदाज किया गया। NREGA के एक भी इश्यु का जवाब नहीं दिया गया। 25 लाख जॉब कार्ड झारखंड में इश्यु हुए। 25 लाख का हमने हिसाब लगाया कि annual labour entitlement, 25 लाख जॉब कार्ड्स का works out to Rs. 2500 crore per year. Material component works out to Rs. 1600 crores. Total works out to Rs. 4,100 crores. पिछले साल 2007-08 में The Government of India provided Rs. 2,000 crores; not Rs. 4,100 crores but only Rs. 2,000 crores. खर्च हुआ 1000 करोड़, Rs. 4,100 crores for 25 lakh job cards! खर्च हुआ 1000 करोड़, तो बेचारा सी.ए.जी. कहां से आंकड़े मैन्युफैक्चर करे? अरुण शौरी जी कह रहे थे, उसने ऐसे बोल दिया। वह बोलेगा ही, क्योंकि वह सच्चाई देखता है। मैं आपको बताता हूं कि झारखंड में यह कहावत है कि नारेगा मतलब मरेगा। जो नारेगा करेगा, वह मरेगा ...**(व्यवधान)**...

सुश्री मैबल रिबैलो: आप गलत बोल रहे हैं, नारेगा मतलब चरागा। NREGA has become 'Chraga'.

श्री यशवंत सिन्हा: अच्छा चरागा ...**(व्यवधान)**... ठीक है। मैं तीसरी बार मैबल जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं। नारेगा मतलब चरागा, आपने कहा है। खुले आम लूट है। उसी तरह सर्व शिक्षा अभियान, कृषि, PMGSY, National Rural Health Mission, Road Construction, बिजली, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, Drinking water, आप और भी किसी यूजफुल सोशल स्कीम की चर्चा कीजिए, सभी का वही हाल है। मैं बजट पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे काबिल दोस्त अहलुवालिया जी उस पर बोलेंगे, लेकिन फेल्ड स्टेट के आप जितने क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं, लॉ एण्ड ऑर्डर हो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वह हो या Left-wing extremism हो, हर फ्रंट पर Jharkhand has unfortunately failed. मुझसे एक दिन पत्रकारों ने पूछा, हम झारखंड की आठवीं वर्षगांठ मना रहे थे, मैं रांची एयरपोर्ट से दिल्ली आ रहा था, उन्होंने पूछा कि आपको क्या कहना है, मैंने कहा आठ साल का गंभीर रूप से बीमार बच्चा, यह झारखंड है। लेकिन गंभीर रूप से बीमार बच्चे के लिए ममता किसके हृदय में है? ममता हमारे हृदय में है, क्योंकि हमने झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाया।

उपसभापति जी, इसलिए नहीं बनाया था कि वह बीमार बच्चा बन जाए।

सुश्री मैबल रिबैलो: आठ साल में क्या हुआ, आपकी गवर्नमेंट कम से कम चार साल थी, आप लोगों ने क्या किया, यह बताइए।

एक माननीय सदस्य: आपने करप्शन करके बीमार कर दिया।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: पांचवें साल में जॉन्डिस हो गया।

श्री यशवंत सिन्हा: आदमी कब गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा, यह कहना मुश्किल है...(व्यवधान)...

सुश्री मैबल रिबैलो: सिन्हा जी ...**(व्यवधान)**... आपकी गवर्नमेंट थी ...**(व्यवधान)**... आप रिस्पोंसिबल रहे ...**(व्यवधान)**... इस डेफिसिएंसी के लिए ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है, यह भी सुन लीजिए ...**(व्यवधान)**... Let him conclude. ...*(Interruptions)*..

श्री यशवंत सिन्हा: इस सदन में फाइनेंशियल बिजनेस के लिए जो विधेयक आया है, उसमें झारखंड का जुलाई तक का "वोट ऑन अकाउंट" लिया जा रहा है। मौसम से हम सभी वाकिफ़ है। झारखंड में जून में बारिश शुरू हो जाती है और इतनी भयानक बारिश हो सकती है कि 15 अक्टूबर तक कोई चुनाव झारखंड में नहीं होगा। 19 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगा, 19 जुलाई को राष्ट्रपति शासन के छह महीने पूरे होंगे। जुलाई भर महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट में पैसे लिए जाते हैं। मैं फिर उस बात पर आता हूं कि हमारी मांग है कि झारखंड में विधानसभा भंग की जाए। मंत्री महोदय, इस सदन में खड़े होकर उत्तर देते समय यह आश्वासन दे कि वे विधानसभा भंग करेंगे और झारखंड विधानसभा का चुनाव लोक सभा चुनाव के साथ कराया जाए। मैं

यही कह रहा हूं कि झारखंड की जनता को अवसर दीजिए। इसमें यदि कोई यह कहे कि यह आपकी नाजायज डिमांड है, ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर जुलाई में छह महीने खत्म हो रहे हैं तो मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि It will be extremely unfair to force the Parliament to extend the President's rule. The Government, by its action, cannot force this sovereign body to take a decision this way or that way. No alternative will be left but to do this.

हमारी तीसरी डिमांड है। पहली यह कि विधान सभा को भंग कीजिए, दूसरी यह कि लोक सभा के साथ चुनाव कराइए और हमारी तीसरी डिमांड यह है कि इस गवर्नर को तुरन्त वापस बुलाइए। जो गवर्नर वहाँ पर अपना personal promotion कर रहा है, झारखण्ड के लोगों के पैसे से अपने राजनीतिक भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहा है, उस गवर्नर को वहाँ पर एक और दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। He must immediately be recalled. उपसभापति महोदय, मैं इस warning के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि अगर * नहीं हटाए गए ...

श्री उपसभापति: नाम को रेकार्ड से हटा दीजिए। आप कृपया गवर्नर बोलिए।

श्री यशवंत सिन्हा: तो* बन कर यहाँ वापस आएंगे।

श्री उपसभापति: नाम को रेकार्ड से हटा दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI YASHWANT SINHA: But I want your ruling on this advertisement. I want you to pronounce on this advertisement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can the Chair ***...(Interruptions)...***

श्री यशवंत सिन्हा: आप direction देते हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI V. NARAYANASAMY: He cannot give it. ***...(Interruptions)...***

SHRI YASHWANT SINHA: What? ***...(Interruptions)...***

SHRI V. NARAYANASAMY: He can't give any ruling on that. ***...(Interruptions)...***

SHRI YASHWANT SINHA: Why not? ***...(Interruptions)...***

श्री पवन कुमार बंसल: सर, इन्होंने एक derogatory शब्द का इस्तेमाल किया है कि वे यह बन कर आएंगे।

श्री उपसभापति: नहीं, वह शब्द रेकार्ड में नहीं आएगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, name should not be quoted by the hon. Member. He is a very senior Member. ***...(Interruptions)...***

SHRI ARUN SHOURIE: The Governor, as the President, acts on the aid and advice of the Council of Ministers. So, the question is whether the Council of Ministers has advised the Governor to advertise himself like that. Is that a fair question? Please answer that question.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, the hon. Member knows the day-to-day functioning is not directed by the Government of India from here. ***...(Interruptions)...***

SHRI YASHWANT SINHA: But what is your ***...(Interruptions)...***

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: That is a different matter. ***...(Interruptions)...***

---

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: During the reply you can make it. ***...(Interruptions)...***

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, I am ***...(Interruptions)...*** but I hope you would not like to use derogatory references for the Governor. He said कि ये बन कर आएंगे ...**(व्यवधान)**...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I am ***...(Interruptions)...***

SHRI ARUN SHOURIE: Don't give us lawyers' answers, Mr. Bansal. Please look at what is happening to the State on your watch. That is the point. ***...(Interruptions)...***

SHRI YASHWANT SINHA: Is the State under watch of the Government of India? ***...(Interruptions)...***

SHRI V. NARAYANASAMY: During the NDA regime how the Governors were used to your own convenience we all know that. ***...(Interruptions)...***

SHRI YASHWANT SINHA: Show one instance where a Governor tried to promote himself personally in this manner. ***...(Interruptions)...*** Show one instance. ***...(Interruptions)...*** आप एक उदाहरण दीजिए कि हमारे regime में किसी गवर्नर ने इस तरह का advertisement दिया. है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेता, कि राज्यपाल महोदय सिसकते हुए दिल्ली लौटेंगे।

श्री प्रशांत चटर्जी: ये लोग बोलेंगे कि हमने नहीं किया और वे लोग बोलेंगे कि हमने नहीं किया। हम लोग middle में हैं।

श्री यशवंत सिन्हा: हाँ, आप middle में हैं, आपने कुछ नहीं किया।

उपसभापति महोदय, इसलिए बहुत दिनों से ...**(व्यवधान)**... बहुत जद्दो-जेहद के बाद हमें झारखण्ड की ओर से अपनी भावनाओं को और अपनी पार्टी की भावनाओं को इस सदन में रखने का मौका मिला है। मैं उत्तर के समय नहीं रह पाऊँगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि एक आवश्यक कार्यक्रम को मैं दो दिनों से postpone कर रहा हूँ, आगे postpone नहीं कर सकता, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो बिन्दु उठाए हैं, दोनों मंत्री महोदय यहाँ पर हैं, वे उनका सही और बिल्कुल सही उत्तर देंगे। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 A.M.

The House then adjourned at thirty-nine minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 26th February 2009.